

रिजर्व बैंक के नेतृत्व के पांच वर्ष - पीछे देखते हुए आगे देखना*

दुव्वुरी सुब्बाराव

सर्व प्रथम; मैं हृदय से नानी पालखीवाला ट्रस्ट (न्यास) को धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर श्री वाई.एच.मालेगम को जो इस ट्रस्ट के अत्यंत प्रतिष्ठित अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही इस वर्ष के पालखीवाला स्मारक व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं कई ख्यातिप्राप्त विचारवान नेताओं को जानता हूँ जिन्होंने विगत वर्षों में यह स्मारक व्याख्यान दिया है। उस अत्यंत चुनिंदा सूची में अपना नाम जोड़ा जाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।

नानी पालखीवाला

2. दिवंगत श्री पालखीवाला से भेंट करने या उनसे बातचीत करने का अवसर मुझे नहीं मिला। 1970 के शुरू में आइएएस सेवा में मेरे आने के समय से ही वे देश में एक प्रतिष्ठित सर्व विदित बुद्धिजीवी के रूप में स्थापित हो चुके थे। किंतु मैं अपने को उन लाखों शिक्षित भारतीयों में शुमार करता हूँ जो भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं को संरक्षण देने के प्रति श्री पालखीवाला की प्रतिबद्ध और जिस बौद्धिक निष्ठा से उन्होंने यह सब किया, उससे प्रभावित थे। अपने छह दशक के कैरियर में उन्होंने एक प्रखर वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई, वे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, विवेकशील वक्ता थे और एक विद्वान डिप्लोमैट थे। वे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो अनेक क्षेत्रों में हमारे सार्वजनिक प्रवचन को प्रभावित करता रहता है।

मेरे व्याख्यान का विषय

3. एक ऐसे प्रसिद्ध सर्व विदित बौद्धिक व्यक्ति की स्मृति में व्याख्यान के लिए उपयुक्त विषय पर मैं बहुत मंथन करता रहा। मैं इस बात से भी सचेत था कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में यह मेरा अंतिम सार्वजनिक व्याख्यान होगा। पालखीवाला का संदर्भ आते ही, यह बात मेरी समझ में आ गई कि प्रजातांत्रिक ढांचे में किसी केंद्रीय बैंक की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व के इर्दगिर्द मेरे विचार केंद्रित होने लगे। केंद्रीय बैंक समष्टि आर्थिक नीति बनाते हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है; फिर भी उनकी व्यवस्था सरकार द्वारा नियुक्त चुने गए

गैर-अधिकारी करते हैं। ऐसी व्यवस्था जान बूझकर की जाती है, जो इस तर्क पर आधारित है कि एक गैर-राजनीतिक केंद्रीय बैंक सांविधिक रूप से निर्धारित जनादेश के अंतर्गत स्वायत्त रूप से कार्य करता है और लंबे समय तक वह रहता है। ऐसी व्यवस्था किसी ऐसी जनतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के लिए प्रति संतुलन का कारगर काम करती है जो एक निर्वाचक चक्र के समय दायरे में राजनीतिक जनादेश से विशिष्ट शैली में काम करती है।

4. एक स्वायत्त और गैर-राजनीतिक केंद्रीय बैंक एक नाजुक व्यवस्था भी है और वह काम तभी करेगा जब केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता का सरकार आदर करे तथा केंद्रीय बैंक भी अपने जनादेश के भीतर रहे, उसी के अनुसार काम करे और अपनी नीतियों तथा कार्रवाइयों के परिणाम के लिए उत्तरदायी हो।

5. आज के व्याख्यान के तीन तत्त्वों को एक साथ संदर्भ में रखकर - भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने और उसके मूल्यों को लागू करने तथा उसकी संस्थाओं के प्रति प्रतिबद्धता के श्री पालखीवाला की अनुकरणीयता की वचनबद्धता - भारत में लोकतांत्रिक महल में रिजर्व बैंक की भूमिका तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा होते देख मैंने तय किया कि श्री पालखीवाला के प्रति मेरा सर्वोत्तम योगदान यह होगा कि मैं एक ऐसे विषय पर अपना ध्यान फोकस करूँ जिसमें उपर्युक्त तीनों तत्त्व एक साथ बुने गए हों। इससे आज का मेरा विषय स्पष्ट है : “रिजर्व बैंक के नेतृत्व के पांच वर्ष : पीछे देखते हुए आगे देखना”।

‘खुशहाल समय में आप जिएं’

6. एक चीनी कहावत है: “खुशहाल समय में आप जिएं”। इसके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं रिजर्व बैंक में पांच वर्ष पहले आया था जब ‘महामंदी’ का दौर चल रहा था और अब मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है जब जब उसका ‘महा बहिर्गमन’ शुरू हो रहा है। पांच वर्षों में इस संकट से एक सप्ताह की भी फुरसत नहीं मिली।

7. केंद्रीय बैंकिंग के दृष्टिकोण से, पिछले पांच वर्षों को इतिहास दो स्पष्ट विकास कार्यों के लिए याद करेगा। पहला, यह कि वैश्विक वित्तीय संकट के प्रति केंद्रीय बैंकों का नीति विषयक जोर का असाधारण प्रदर्शन करना। इससे गैर-परंपरागत मौद्रिक नीतियों के अल्पावधि एवं दीर्घावधि प्रभाव के बारे में जोरदार चर्चा छिड़ गई। इसके साथ ही, उनकी नीतियों का दूसरे देशों पर प्रभाव के बारे में केंद्रीय बैंकों के उत्तरदायित्व पर भी बहस छिड़ गई। दूसरा, वह ऐतिहासिक मार्कर तौर-तरीका होगा जिसमें संकट की सीखों का प्रकटन वह जनादेश, स्वायत्तता तथा केंद्रीय बैंकों की जिम्मेदारी के बारे में दुनिया-भर के कई देशों में पुनः

* 21 अगस्त 2013 को; मुंबई में डा. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, का दसवां नानी ए. पालखीवाला स्मारक व्याख्यान।

परिभाषित किया जा रहा है। सभी प्रकार के तनावों और स्वीकृत रूप से चुनौती-भरे समय के दौरान नीति-व्यवस्था की चिंताओं के बावजूद, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बौद्धिक रूप से शक्ति-संपन्न ऐसी अवधि में विश्व में सबसे अच्छे बैंकों में से एक का नेतृत्व करने का सुयोग मुझे मिला।

8. उस संदर्भ में; आज मैं अपने व्याख्यान “रिजर्व बैंक के नेतृत्व के पांच वर्ष: पीछे देखते हुए आगे देखना” को दो खंडों में विभाजित करना चाहता हूँ। पहले खंड में समष्टि आर्थिक विकास का अपना मूल्यांकन और उस पर रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। दूसरे खंड में, भविष्य में रिजर्व बैंक के सामने मूल्य चुनौतियों के बारे में चर्चा करूँगा।

I. विगत पांच वर्षों में समष्टि आर्थिक विकास और भारिबैंक की प्रतिक्रिया

9. विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए विगत पांच वर्षों में समष्टि आर्थिक विकास को तीन स्पष्ट चरणों में विभजित किया जा सकता है: (i) वैश्विक वित्तीय संकट और भारिबैंक की प्रतिक्रिया, (ii) इस संकट और भारिबैंक की वृद्धिकारी मुद्रास्फीति के व्यवहार के साथ संघर्ष और (iii) बाहरी क्षेत्र का वह दबाव जो पिछले कुछ माह से बढ़ गया है तथा करेंसी बाजार में भारिबैंक के स्थिरता लाने के लिए प्रयास।

प्रथम चरण (2008-09) - संकट प्रबंधन

10. तब से अब बहुत कुछ बीत गया है, 2008 का लेहमान संकट लगता है दीर्घकालिक है। फिर भी, यह बात वास्तविक है कि गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के दो सप्ताह के भीतर ही इस संकट का सामना मुझे करना पड़ा। मेरे कहने का यहां आशय यह नहीं है कि उन दिनों घटनाओं को नए सिरे से प्रस्तुत किया जाए, बल्कि उस प्रयास एवं उस संकट को संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए और इसीलिए उनके प्रति यह नीति विषयक प्रतिक्रिया है।

11. उस संदर्भ की सराहना करने के लिए आप को 2008 के उन बुरे दिनों को याद करना होगा। याद करें कि भारत आगामी चमत्कारिक अर्थव्यवस्था को नया रूप देने के कगार पर था। उसकी वृद्धि दर 9 प्रतिशत पर थी। राजकोषीय घाटा सुधर रहा था। रुपया मजबूत हो रहा था और परिसंपत्ति की कीमतें बढ़ रही थीं। मुद्रास्फीति के दबाव थे किंतु आम धारणा मुद्रास्फीति की सफलता का समस्या थी, न कि विफलता की। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी यह सोच थी कि हमने इन दोनों को अलग कर दिया। यदि उन्नत अर्थव्यवस्था में गिरावट भी आई तो उभर रही बाजार अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित नहीं होगी क्योंकि उनका समष्टि आर्थिक प्रबंधन उन्नत किस्म का है, भारी-भरकम विदेशी

आरक्षित भंडार उनके पास है तथा उनके बैंकिंग क्षेत्र बहुत सुदृढ़ हैं।

12. यदि इस संकट से पूरी तरह से हमारी साख नहीं गिरी, तो भी इसने संबंध विच्छेद की परिकल्पना पर आघात तो किया ही। भारत-सहित संभवतः दुनिया का प्रत्येक देश इससे प्रभावित हुआ। भारत में इसका असर क्यों हुआ? कारण यह है कि 2008 तक दोहरे व्यापार (वाणिज्य वस्तु के निर्यात एवं आयात) के लिए हमारी मान्यता की तुलना में भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी एकीकृत थी। पिछले दशक की तुलना में जीडीपी के अनुपात में यह दोगुने से ज्यादा था अर्थात् 1998-99 में लगभग 20 प्रतिशत रहा जबकि एशियाई संकट के वर्ष 2008-09 में यह 40 प्रतिशत से ज्यादा था। यही वर्ष वैश्विक संकट का वर्ष था।

13. यदि हमारे व्यापार का एकीकरण गहरा था तो हमारा वित्तीय एकीकरण और भी गहरा था। वित्तीय एकीकरण का पैमाना जीडीपी की तुलना में कुल विदेशी लेनदेन का अनुपात है (सकल चालू खाता की राशियां और सकल पूंजी खाता की राशियां)। यह अनुपात 1998-99 में जहां 44 प्रतिशत था, वहीं 2008-09 में वह इसके दोगुने से भी ज्यादा अर्थात् 112 प्रतिशत था। इसी बात से भारत के वित्तीय एकीकरण की गहराई का पता चलता है।

14. इसका अर्थ यह था कि वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति डांवांडोल थी। हम व्यापार, वित्त एवं विश्वास चैनलों के माध्यम से प्रभावित थे। इस संकट के प्रति रिजर्व बैंक ने तुरंत कार्रवाई की। उसकी नीतियों ने अपने वित्तीय बाजारों को संचालित रखे। उनमें रुपए की पर्याप्त तरलता बनी रही और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रवाह उसने बनाए रखा।

संकट प्रबंधन से सीख

15. जैसा कि किसी ने कहा है। यह संकट इतना महत्वपूर्ण था कि यह बेकार नहीं गया। ऐसे समय में, संकट प्रबंधन से हमें कई प्रकार की सीख मिली। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सीखों पर ही मैं यहां चर्चा करूँगा। पहला, हमने यह सीखा कि ऐसी अनिश्चितता तथा अपूर्वानुमेयता के वैश्विक वातावरण में नीति संबंधी कार्रवाई तुरंत, निश्चित तथा पुनः विश्वास पैदा करनेवाली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संकट के समय यदि सरकारें तथा केंद्रीय बैंक कार्रवाई करते हैं तो इससे सहायता मिलती है और लगता है कि मिलकर कार्रवाई की गई है। दूसरा, हमने यह सीखा कि कार्रवाई महत्वपूर्ण है। किंतु संवाद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आर्थिक वातावरण अनिश्चित होता है, तब बाजार के खिलाड़ी, आर्थिक एजेंट पुनः विश्वास एवं तत्परता दोनों के लिए सरकारों और केंद्रीय बैंकों की तरफ देखते हैं। वास्तव में, संवाद भारत-

सहित सभी केंद्रीय बैंकों के लिए एक अत्यंत आवश्यक औजार था जिसे 2008 के उन संकटपूर्ण दिनों में अपनाया गया।

16. तीसरी सीख जो हमने सीखी वह यह है कि बहुराष्ट्र संकट में भी सरकारों तथा केंद्रीय बैंकों को घरेलू स्थितियों के प्रति अपने दायित्व का पालन करना होगा। प्रत्येक देश पर एक अनोखे प्रकार का दबाव है कि वे अन्य देशों के संकट-दायित्व को नकल करें, विशेषकर उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश की। उदाहरण के लिए, उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों को अपनी मौद्रिक शक्तों में ढील देनी पड़ी; मुद्रास्फीति की आकांक्षाओं को बढ़ाना पड़ा और असली ब्याज दरों को कम करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा ताकि वे परिमाणात्मक रूप में ढिलाई करें। उभर रहे बाजार के लिए क्या केंद्रीय बैंकों को ऐसा करने की कोई जरूरत थी? मेरा मानना है कि ऐसी जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त परंपरागत साधन अभी बचे थे। इसके स्थान पर, हमें यह दिखाना चाहिए था कि हम इसका प्रयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

17. संकट के विषय पर मैं भी आपकी दुविधा के साथ अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। संकट प्रबंधन प्रतिशत का एक खेल है। जो हम सोचते हैं उसे हमें करना होगा। इस गति को उलटने का यही सर्वोत्तम अवसर है। इसके साथ ही, नैतिक संकट-सहित दीर्घावधि परिणामों की तुलना में अल्पावधि हितों को हमें तौलना होगा, 2008 में, बड़ी मात्रा में चलनिधि बाजार में झोंक देना सर्वोत्तम दाव के रूप में माना जाता था। वास्तव में, अनजान क्षेत्र में, अति सावधान का अर्थ है जिसे पर्याप्त समझा गया है उसकी अपेक्षा ज्यादा तरल निधि सिस्टम में प्रदान की जाए। इस प्रकार की रणनीति अल्पावधि में कारगर थी, किंतु घटना के बाद के विचार की दृष्टि में, हमें मालूम है कि अधिक मात्रा में तरल निधि से मुद्रास्फीति के दबाव और बढ़ सकते हैं। संकट के बीच न्याय की यह मांग है कि किसी बिंदु पर संभावित मुद्रास्फीति की लागत की अपेक्षा संकट को रोकने से होनेवाले फायदे के संतुलन के बारे में हमें सोचना होगा। याद रहे कि हम तत्काल समय में कार्रवाई कर रहे थे। जो विश्लेषक हमारी आलोचना कर रहे हैं वे घटना घटित के बाद के फायदे से ऐसा कर रहे हैं।

दूसरा चरण (2010-11) संकट से मुक्ति

18. भारत अन्य उभर रही अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा शीघ्र ही इस संकट से पार पा गया, किंतु अन्य स्थानों की अपेक्षा शीघ्र ही यहां मुद्रास्फीति भी बढ़ गई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से मापी गई मुद्रास्फीति, जो 2009 के मध्य में थोड़े समय के लिए असल में नकारात्मक सीमा में चली गई थी, 2009 के आखिर में बढ़नी शुरू हो गई और पूरे 2010 में तथा 2011 के अधिकांश समय में 9-10 प्रतिशत के आसपास रही जिससे

मांग एवं पूर्ति के दबावों का पता चलता है। पूर्ति के दबाव घरेलू खाद्यान्न कीमतों के बढ़ने से और तेल की वैश्विक कीमतों एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि होने से बढ़े। मांग दबाव आय में बढ़ोतरी से तथा स्थिति में सुधार शुरू होने से प्रतिबंधित मांग के एकाएक मुक्त होने से बढ़ोतरी होने लगी। आपूर्ति के आघात एवं मांग के दबाव ने मिलकर व्यापक मुद्रास्फीतिकारी प्रक्रिया को तेज कर दिया। हम वृद्धि तथा मुद्रास्फीति संतुलन के सर्वाधिक मूर्त रूप केंद्रीय बैंकिंग दुविधा में फंस गए।

19. मुद्रास्फीति के दबावों के प्रतिक्रिया स्वरूप; रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2009 के शुरू में ही अपने संकट प्रेरित समंजनकारी मौद्रिक नीति को उलट दिया और उसे कड़ा करना शुरू किया। अपने मुद्रास्फीतिकारी कदम के लिए हमारी आलोचना की गई। विडंबना यह कि यह काम दो विपरीत दिशाओं से हुआ। एक तरफ वे आलोचक थे जिनका कहना था कि मुद्रास्फीति के बारे में हम बहुत ही नरम थे, यह भी कि मुद्रास्फीति के दबावों की पहचान करने में हमने देर कर दी और ऐसे दबावों की पहचान के बाद भी इसे कसने के लिए हमने जो छोटा कदम उठाया वह एक भीरु और संकोची प्रतिक्रिया थी। यदि रिज़र्व बैंक तेजी से तथा और निर्णायक कार्रवाई करता तो मुद्रास्फीति को काफी पहले ही नियंत्रण में कर लिया गया होता। तस्वीर के दूसरी ओर से, हमारी आलोचना बहुत ज्यादा आक्रामक होने के लिए की गई। मुख्य रूप से इस तर्क के आधार पर कि ज्यादातर खाद्य पदार्थों एवं आपूर्ति आघात के कारण मुद्रास्फीति के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना रिज़र्व बैंक के लिए कोई जरूरी नहीं था, और बिना मुद्रास्फीति दबावों को कम किए हम दमघोंटू वृद्धि तक ही सीमित रह गए।

20. परिदृश्य के दोनों छोर से आए इस आलोचना का मैं उत्तर देना चाहूंगा।

21. जो लोग यह कहते हैं कि इस वक्र (मोड़) के पीछे हमारा हाथ है। मेरा सरल उत्तर है कि वर्ष 2010 एवं 2011 के संदर्भ को याद करें। विश्व का अधिकांश भाग अभी संकट की स्थिति में था; यूरोजोन का संकट तो पूरे उफान था और वैश्विक रूप से काफी अनिश्चितता थी। और जैसा कि हमने 2008 के लेहमान की घटना के अनुभव से सीखा है, हम विपरीत बाहरी उतार-चढ़ावों के प्रति असुरक्षित बने रहे। इसलिए हमारे छोटे कदम एक ओर वृद्धि को बनाए रखने तथा दूसरी ओर मुद्रास्फीति को रोकने के बीच नाजुक संतुलनकारी थे।

22. यह सच है कि पीछे के अनुभव का फायदा हमें मिला। मैं पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करता हूँ कि अर्थव्यवस्था की और बेहतर ढंग से सेवा की जा सकती थी बशर्ते कि हमारी मौद्रिक सख्ती और पहले शुरू की गई होती और वह भी अपेक्षाकृत तीव्र

एवं मजबूती से। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कि अब हमें पता है कि इस संकट से उबरने के लिए हमारे पास क्लासिक (पुराना) V-आकार की रिकवरी थी जिससे लेहमान संकट के वर्ष में हमारी वृद्धि बहुत नीचे नहीं आई अर्थात् उतनी नीचे नहीं जितनी की हमें डर था, और वह वृद्धि बाद के दो वर्षों में पहले की सोच की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत थी। लेकिन याद रहे, यह सब बाद की सूझ है जबकि हम तत्काल समय में नीति तैयार करते थे जो उस समय ज्ञान की दुनिया के भीतर प्रचलित था। मुख्य मुद्दे से अलग हटकर, यह घटना कारगर मौद्रिक नीति की क्रमिक बढ़ोतरी के लिए तीव्रतर एवं अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय आर्थिक डाटा के महत्त्व को उजागर करती है।

23. अब मैं उन शांति प्रिय लोगों को उत्तर देना चाहता हूँ जो यह तर्क देते हैं कि रिजर्व बैंक अपने मुद्रास्फीति के विरुद्ध के मामले में बहुत ही आक्रामक था।

24. सर्व प्रथम; मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को रोकने में विफल रहा और इसमें केवल दमघोंटू वृद्धि ही हुई। थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति दो अंकों से घटकर लगभग 5 प्रतिशत पर आ गई, मूल मुद्रास्फीति गिरकर लगभग 2 प्रतिशत पर रह गई। हां, वृद्धि में संतुलन बना रहा, किंतु सख्त मौद्रिक नीति को ही इस संतुलन का पूरा श्रेय देना गलत (अनुचित) होगा, और इससे बढ़कर यह कि नीतिगत पाठ के रूप में यह भ्रामक है। भारत की आर्थिक गतिविधि में शिथिलता आपूर्ति के अवरोधों एवं प्रशासनिक मुद्दों के कई कारणों से आई। यह बात स्पष्ट रूप से रिजर्व बैंक की सीमा से बाहर थी। यदि रिजर्व बैंक की रेपो दर ही वृद्धि दिखाने के लिए एकमात्र कारक था तो अप्रैल 2012 तथा मई 2013 के बीच 125 आधार बिंदु की हमारी दर कटौती सीआरआर में 200 आधार बिंदु की कटौती तथा विगत वर्ष में ₹1.5 ट्रिलियन की खुले बाजार लेनदेनों में कटौती के प्रति वृद्धि की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी।

25. निश्चय ही, कुछ वृद्धि में कमी का श्रेय मौद्रिक सख्ती को दिया जा सकता है। यह बात नोट की जाए कि मौद्रिक सख्ती का उद्देश्य सकल मांग को कम करना है और इसलिए वृद्धि में कुछ त्याग को मौद्रिक सख्ती में शामिल किया गया। किंतु इस प्रकार का त्याग केवल अल्पवधि में है, मध्यावधि में कोई त्याग नहीं है। असल में, वृद्धि को बनाए रखने के लिए कम एवं निरंतर मुद्रास्फीति एक आवश्यक पूर्व शर्त है। अल्पावधि में किसी प्रकार की वृद्धि को त्याग देना निरंतर मध्यावधि में वृद्धि द्वारा बराबर करने की तुलना में ज्यादा होगा। मैं इस बात पर पुनः जोर देना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक ने सख्त मौद्रिक नीति इसलिए नहीं अपनाई कि उसे वृद्धि की चिंता नहीं है बल्कि इसलिए कि उसे वृद्धि की चिंता है।

26. हमारी मौद्रिक सख्ती के आलोचकों को यह बात भी अवश्य नोट करनी चाहिए कि 2009-12 के दौरान सरकार के ढीले राजकोषीय कदम से स्वतंत्रता की हमारी मात्रा कम कर दी गई। यदि राजकोषीय समेकन तीव्र गति से हुआ होता तो यह संभव है कि मौद्रिक नीति का क्रमांकन कम सख्त हुआ होता।

27. अब मैं उस आलोचना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ जो मौद्रिक नीति आपूर्ति-आघातों के विरुद्ध एक कारगर हथियार है। यह एक अवधि-रहित एवं समय-रहित मुद्दा है। मैं पहला गवर्नर नहीं हूँ जिसने इस पर प्रतिक्रिया दी है, और मैं जानता हूँ कि अंतिम भी नहीं हूँ। मेरी प्रतिक्रिया को आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। 1500 डालर प्रति व्यक्ति की अर्थव्यवस्था वाले - जहां व्यय-समूह का बड़ा हिस्सा खाद्यान्न है - देश में खाद्यान्न स्फीति तुरंत मजदूरी-स्फीति को प्रभावित करती है, और इसीलिए मुख्य मुद्रास्फीति होती है। असल में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का संप्रेषण संस्थागत रूप ले चुका है जहां मनरेगा की मजदूरी औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति को सूचकांकित करती है। इसके अलावा, जब खाद्यान्न व्यय-समूह का इतना बड़ा हिस्सा है तो निरंतर खाद्यान्न स्फीति से स्फीतिकारी उम्मीदों में तेजी आना लाजमी है।

28. जैसा की हुआ है; इन दोनों कारकों ने अपना काम किया - मजदूरी तथा मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं बढ़ने लगीं। ऐसा ज्यादातर उपभोग-चालित वृद्धि, भारी राजकोषीय घाटे तथा वर्धित कार्यान्वयन अवरोध के किसी संदर्भ के विरोध में यह सब हुआ। यदि मूल मुद्रास्फीति के बढ़ने का कोई प्रबल कारण था तो वह यही था। 2010 के शुरु में यह वृद्धि 3 प्रतिशत के नीचे से बढ़ते-बढ़ते अगले वर्ष के अंत तक लगभग 8 प्रतिशत हो गई। यह वही पृष्ठभूमि है जिससे 2010 एवं 2011 में हमारी मुद्रास्फीति-विरोधी पहल का मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है।

तीसरा चरण (2012-13) - विदेशी क्षेत्र में दबाव

29. याद रहे, मैंने अपना व्याख्यान इस चीनी कहावत से शुरु किया था - “खुशहाल समय में आप जिएं”। अतः, जैसे-जैसे मुद्रास्फीति में वृद्धि के समर्थन में मौद्रिक स्थिति में ढील देने के लिए संतुलन शुरू हो गया, हम विगत दो वर्षों में विदेशी क्षेत्र में उलझते गए और पिछले तीन माह से रुपए में तीव्र अवमूल्यन होने लगा। अवमूल्यन की इस तीव्रता के बारे में निराशा रही है, इस बात की बढ़ती प्रवृत्ति भी रही है कि इन सबका कारण अमरीकी फेडरल द्वारा उसकी अति सरल मौद्रिक नीति में छेड़छाड़ को दिया जाता है।

30. मेरा विश्वास है कि ऐसा निदान भ्रम में डालनेवाला है। निश्चय ही, रुपए के अवमूल्यन की तीव्रता एवं समय के कारण अमरीकी फेडरल द्वारा ‘छेड़छाड़’ में बाजार के तत्त्व हैं बशर्ते

कि हम इसे स्वीकार न करें कि इस समस्या का मूल कारण घरेलू ढांचागत कारक है।

31. ये ढांचागत कारक क्या हैं? इसकी जड़ में समस्या यह है कि हमारा चालू खाता घाटा लगातार तीन वर्षों से बनाए रखने लायक स्तर से काफी ऊँचा बना रहा और इस चौथे वर्ष में भी वही स्थिति रही। चालू खाता घाटे का वित्तपोषण हम इसलिए करते रहे कि वैश्विक प्रणाली में आसान तरलता थी। यदि हम उस अवकाश - समय का उपयोग किए होते, जिसने ढांचागत कारकों पर ध्यान देने का हमें मौका दिया और चालू खाता घाटा को कम करके उसके धारणीय स्तर पर ला दिया, तो इस छेड़छाड़ को झेलने में हम समर्थ होते। उस समय हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए एकाएक रुकने के लिए हमने अपने को असुरक्षित कर दिया और वैश्विक भावुकता के कारण हमारी पूंजी बाहर चली गई, समायोजन की अंतिम लागत भी तेजी से बढ़ गई।

32. लेकिन चालू खाता घाटा क्यों इतना ऊँचा गया? आधारभूत अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि चालू खाता घाटा उस समय बढ़ता है जब सकल मांग सकल आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है। यह तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार की सोच, वृद्धि में तीव्र गिरावट की स्थिति में, वर्तमान समय में हम पर लागू नहीं होती। किंतु हमें यह मानने की जरूरत है कि कम वृद्धि के वातावरण में भी चालू खाता घाटा काफी बढ़ सकता है बशर्ते कि आपूर्ति ने वृद्धि एवं विदेश व्यापार दोनों पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव डाला हो, जैसा कि हमारे साथ हुआ है।

33. हमारे बाहरी क्षेत्र की समस्या का पक्का समाधान केवल यह है कि हम अपने चालू खाता घाटे को कम करके उसे धारणीय स्तर पर बनाए रखें और घटे हुए चालू खाता घाटे का वित्तपोषण स्थिर एवं यथा संभव सीमा तक ऋणोत्तर पूंजी प्रवाह से करें। चालू खाता घाटे को कम करने के लिए ढांचागत समाधान अपेक्षित है। इस जरूरी ढांचागत समाधान के लिए भारिबैंक के पास बहुत थोड़ी नीतिगत जगह या लिखतें हैं। ये सरकार के दायरे में आते हैं। ढांचागत समाधान में भी समय लगेगा। अंतरिम समय में, हमें बाजार के उतार-चढ़ाव को स्थिर करने की जरूरत है। यह एक ऐसा कार्य है जो रिज़र्व बैंक के कार्यक्षेत्र में आता है।

34. रिज़र्व बैंक की यह दृढ़ नीति है कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर को लक्ष्य न किया जाए और हम उस नीति की सच्चाई पर खड़े हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारा प्रयास, खासकर विगत तीन माह में, उतार-चढ़ाव को संतुलित करना रहा है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय दर बाजार से अपने तयशुदा स्तर पर समायोजित हो जाती है ताकि समाधान की शर्तवत् लागत का बोझ फर्मों, परिवारों तथा बैंकों के लिए कम पड़े।

35. इस बात की आलोचना होती रही है कि रिज़र्व बैंक के नीति विषयक कदम भ्रम पैदा करनेवाले रहे रहें और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को रोकने में उसमें संकल्प की कमी देखी गई। सबसे पहले मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए हमारी वचनबद्धता पूर्णरूपेण और असंदिग्ध है। मैं मानता हूँ कि हमने अपने उपायों का कारण (तर्क) बहुत कारगर तरीके से संप्रेषित कर दिया है।

36. हमारी कार्यवाहियों में सामंजस्य था। हमारे पूंजी खाता के उपायों का उद्देश्य देश में बाहर से आनेवाली पूंजी को बढ़ावा देना तथा देश से बाहर जाने वाली पूंजी को हतोत्साहित करना था। यह भी कि हमने अल्पावधि धन की लागत जुटाने के लिए चलनिधि को सख्त बनाया ताकि उतार-चढ़ाव पर रोक लगे। इसके साथ ही, हमने अल्पावधि से दीर्घावधि तक ब्याज दर के संकेत को संप्रेषित करने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र को ऋण प्रवाह में बाधा आएगी। अतः हमने 'प्रचालन मोड़' का भारतीय संस्करण शुरू किया।

37. मैं यहां इस बात को अवश्य दोहराना चाहता हूँ कि पूंजी नियंत्रण करना या पूंजी खाता उदारीकरण की दिशा को उलटना रिज़र्व बैंक की नीति नहीं। यह बात उल्लेखनीय है कि अनिवासियों द्वारा भारत में पूंजी लाने या यहां से पूंजी बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के उपाय हमने नहीं किए।

II. रिज़र्व बैंक के लिए भारी चुनौतियां

38. अब मैं अपने व्याख्यान के दूसरे भाग पर आता हूँ। विगत पांच वर्षों से कई बार, भाविष्य के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक की चुनौतियों के बारे में मुझ से पूछा जाता रहा। चूंकि इस महान संस्था के गवर्नर के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त पर है, इसलिए यह प्रश्न मेरे दिमाग में बार-बार घूमता रहा है। मैं पूरी तरह से इस बात के लिए सजग हूँ कि यह कोई सेमिनार नहीं है, इसलिए मैं, केवल संक्षेप में उन चारों चुनौतियों पर प्रकाश डालूंगा जिनके बारे में रिज़र्व बैंक को विचार करने की जरूरत है ताकि वह एक प्रमुख नीति निर्माता संस्था बनी रही।

वैश्वीकरण विश्व में प्रबंधन - नीति

39. मेरी सूची में रिज़र्व बैंक के लिए पहली चुनौती आर्थिक एवं विनियामक नीतियां दोनों को वैश्वीकरण विश्व में प्रबंध करना सीखना है। वैश्विक वित्तीय संकट, यूरोजोन सार्वभौम ऋण संकट तथा विगत कुछ माह से करेसी बाजार के उतार-चढ़ाव ने इस बात का जोरदार प्रदर्शन किया है कि किस प्रकार जटिल, अनिश्चय तथा यहां तक की मनमौजी ढंग से हमारे घरेलू समष्टि आर्थिक स्थिति को विदेशी गतिविधियों ने प्रभावित किया

है। अपनी नीतियों को तैयार करने में, हमें विदेशी गतिविधियों को ध्यान में रखना होगा, विशेषकर हमारे समष्टि अर्थव्यवस्था पर उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों की नीतियों का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसका महत्त्व ज्यादा ही होगा क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत का एकीकरण बढ़ रहा है। निश्चय ही, वैश्वीकरण दोधारी तलवार है। इसमें लागत लगती है और लाभ भी मिलता है। रिजर्व बैंक को अपनी विश्लेषणात्मक तथा बौद्धिक कठोरता को धारदार बनाने की जरूरत है ताकि वह ऐसी नीतियां बनाए जो वैश्वीकरण के फायदों का दोहन करे और अपने जोखिम समाप्त करे।

40. विगत पांच वर्षों में, एक संस्था के रूप में वैश्विक विश्व में प्रबंधन नीति के बारे में हमने बहुत-कुछ सीखा है। फिर आगे का शिक्षण-वक्र बहुत ही ऊंचा है। मेरी इच्छा है कि वैश्विक विश्व में कैसे उभर रहे बाजार में केंद्रीय बैंक नीतियों का प्रबंधन करता है, इसके लिए रिजर्व बैंक को चाहिए कि मानक तय करने में वह नेतृत्व प्रदान करे। दूसरे शब्दों में, हमको सर्वोत्तम प्रथा वाला होना चाहिए जिसका अनुकरण अन्य केंद्रीय बैंक करें।

ज्ञानवान संस्था

41. चुनौतियां की मेरी दूसरी सूची यह है कि रिजर्व बैंक को स्वयं को एक ज्ञानवान संस्था की स्थिति में अवश्य रखना चाहिए। पिछले संकट से यह पता चला है कि ज्ञानवान का महत्त्व है। वे केंद्रीय बैंक, जो डोमेन (क्षेत्र विशेष) ज्ञान में अग्रणी हैं और नीतियों तथा कार्रवाइयों के रूप में सीमा पर कर रहे हैं, निरंतर सक्रिय एवं परस्पर जुड़े विश्व में समष्टि आर्थिक प्रबंधन की जटिलताओं से निपटने में बेहतर रूप से समर्थ हैं।

42. ज्ञानवान संस्था होने के लिए स्पष्ट रूप से न तो कोई माडल या नियम पुस्तक है, न ही विशेषताओं की कोई विस्तृत सूची है। ज्ञानवान संस्था होना विश्व में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रायः इसे अपने देश के संदर्भ में उपयुक्त होने के लिए उन्हें पुनः आविष्कृत करना, सीमा को पार करना, प्रश्न पूछना, खुले दिमाग का होना, संव्यावसायिकता के साथ कार्रवाई करना तथा ईमानदारी एवं किसी ऐसी संस्थागत संस्कृति को प्रोत्साहन देना जिसका रास्ता क्रमबद्धता अनुसार तय होता है। रिजर्व बैंक को अपनी एचआर नीतियों की समीक्षा करने की भी जरूरत है ताकि वह एक प्रतिभा निधि निर्मित कर जो आगामी चुनौतियों का सामना कर सके।

अद्यतन विकास की जानकारी रखना

43. 2008 में जब मुझे रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया तब यहां का कार्यभार लेने से पहले मैंने प्रधानमंत्री से भेंट की

थी। जैसाकि हम सभी जानते हैं, वे बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मेरे दिमाग में घर कर गई: “सुब्बाराव, आइएएस में अपना दीर्घकालीन अनुभव लेकर रिजर्व बैंक में आप जा रहे हैं। रिजर्व बैंक में, असली दुनिया से संपर्क में न रहने का जोखिम है, वहां आपके दिमाग में हमेशा ही ब्याज दरें, चलनिधि का जाल तथा मौद्रिक नीति के संप्रेषण-जैसे मुद्दे पूरी तरह छाये रहेंगे। यह भूल जाना आसान है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य भूख तथा कुपोषण को कम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, नौकरियां निर्मित करना, सड़कें तथा पुल बनाना और हमारे खेतों एवं फर्मों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना भी है। आप अद्यतन विकास की जानकारी रखें।”

44. रिजर्व बैंक में अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में, मैंने इस विवेकपूर्ण सलाह का अपनी पूरी योग्यता के साथ पालन किया। हमने अनेक प्रकार की पहल की शुरुआत की है। जिस गांव में असहाय लोगों के लिए कार्यक्रम था वहां रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारियों ने दौरा किया, हमारे नवयुवक अधिकारियों के लिए ग्राम तल्लीनता कार्यक्रम, फोकस समूह के साथ टाउन हाल प्रदर्शनी तथा बैठकें, अग्रिम पंक्ति के मैनेजर्स के साथ सम्मेलन, कारबारी पत्रकारों की सभा की गई। कुछ ऐसे ही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गिनाए जा सकते हैं।

45. इन सभी पहलों के फलस्वरूप; रिजर्व बैंक आज पहले की अपेक्षा काफी सचेत है ताकि जिन नीतियों को उसने बनाया है वे फलदायी केवल तभी हो सकती हैं जब असली दुनिया में वे सकारात्मक अंतर ला सकें। उदाहरण के लिए, रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति-विरोधी कदम कोर (मुख्य) चिंताओं में से एक है क्योंकि मुद्रास्फीति से लोग आहत होते हैं। इसकी ज्यादा चोट खुशहाल लोगों की तुलना में गरीब लोगों को लगती है। किंतु गरीब लोग संगठित नहीं हैं, वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते। एक जन-नीति संस्था के रूप में, रिजर्व बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह ‘गरीब जनता की मौन आवाज’ सुनने के लिए अतिरिक्त प्रयास करे।

46. सीमा से परे जाना कोई अलग कार्य नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, रिजर्व बैंक की नीतियों का प्रभाव लोगों के प्रतिदिन की जिंदगी पर पड़ता है। रिजर्व बैंक एक उपयोगी एवं सुसंगत संस्था केवल तभी रहेगी जब वह सामान्य लोगों की आशाओं एवं आकांशाओं को समझने में समर्थ हो और अपनी नीति में उन्हें शामिल करे।

स्वायत्तता और उत्तरदायित्व

47. विगत पांच वर्षों के संकट ने केंद्रीय बैंकों के बारे में कतिपय मूलभूत प्रश्न उठाए हैं - उनके जनादेश, उनकी स्वायत्तता की सीमा और उनके काम करने के तौर-तरीके जिनके माध्यम से वे

अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। ये प्रश्न भारत में भी उठते रहे हैं। कई समितियों ने सुझाव दिए हैं कि रिज़र्व बैंक का जनादेश इस तर्क पर आधारित होना चाहिए कि वर्तमान में इसे दिया गया व्यापक जनादेश मूल्य स्थिरता-मौद्रिक नीति की मुख्य चिंता - इसके फोकस को कम कर रहा। वित्तीय क्षेत्र विधायी संशोधन आयोग (एफएसएलआरसी) ने इस वर्ष मार्च में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह तर्क दिया गया है कि रिज़र्व बैंक को दिया गया जनादेश मौद्रिक नीति और बैंक विनियम एवं भुगतान प्रणाली तक सीमित होना चाहिए।

48. केंद्रीय बैंक के जनादेश के बारे में, यह बात ध्यान में रखनी है कि मूल्य स्थिरता के अनुसरण में वित्तीय स्थिरता को नकारने के लिए केंद्रीय बैंक वैश्विक वित्तीय संकट के लिए एक शाक्तिशाली धक्का है। इस संकट के तत्काल बाद, जिसने यह देखा कि अमरीकी फेडरल बैंक तथा अन्य केंद्रीय बैंकों ने भारी चलनिधि रकम प्रदान किया और उन्होंने अपरंपरागत हाथियारों का प्रयोग किया, यह बात सर्वसम्मति से उभर आई कि मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में स्पष्टता की जरूरत है। इसके बाद यूरोजोन ऋण संकट ने यूरोपीय केंद्रीय बैंकों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि उन्हें सरकारों को बचाने के लिए अपने जनादेश में संशोधन एवं विस्तार करना पड़ा। संक्षेप में, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी केंद्रीय बैंक, जो वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, सरकारी ऋण की संपोषिता को मना नहीं कर सकता। इसे दूसरी तरह से देखें, एकल उद्देश्य (मूल्य स्थिरता) लेकर चलनेवाले किसी केंद्रीय बैंक का रुढ़िवादी विचार और एकल साधन (अल्पावधि ब्याज दर) का पूरी दुनिया में पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है।

49. अभी अनिश्चय की स्थिति है; लेकिन हर ओर से यह विचार बन रहा है कि अब केंद्रीय बैंकों को मूल्य स्थिरता तथा सरकारी ऋण की धारणीयता में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। बड़ा प्रश्न यह है कि इस कैसे प्राप्त किया जाए।

50. यह बात स्पष्ट है कि इसका कोई सरल उत्तर नहीं है। कुछ ऐसे मत हैं जो इस मुद्दे पर विचार करने के लिए अवश्य सोचते हैं। पहला, केंद्रीय बैंकों का मूल उत्तरदायित्व मूल्य स्थिरता के बारे में समझौता नहीं करना होना चाहिए। दूसरा, केंद्रीय बैंकों को वित्तीय स्थिरता के बारे में अग्रणी होना चाहिए, लेकिन उन्हें केवल ऐसा ही नहीं करना चाहिए। तीसरा, सरकारी ऋण की धारणीयता के लिए केंद्रीय बैंक के उत्तरदायित्व की सीमाएं साफ-साफ परिभाषित की जानी चाहिए। चौथा, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के बारे में सरकार को यह दायित्व सामान्य तौर पर विनियामकों पर अवश्य छोड़ देना चाहिए। केवल संकट के समय उसे एक सक्रियवादी की भूमिका में रहना चाहिए।

51. इस संकट ने केंद्रीय बैंकों के लिए और विस्तृत भूमिका का मामला मजबूत बना दिया है। क्या हम इन सबको अनदेखा कर सकते हैं और इस पुरानी समझ को ही लेकर चलेंगे कि रिज़र्व बैंक के प्रेषण एवं प्रभाव क्षेत्र को बदलने के लिए किसी केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ऐसी बात इष्टतम से नीचे, यहां तक की जोखिम-भरी भी हो सकती है।

52. इस सबसे संबंधित प्रश्न रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता की सीमा के बारे में है और यह कि कहां और किस सीमा तक इसे कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। अंततोगत्वा, रिज़र्व बैंक की नीतियों के परिणामों के लिए उसकी जिम्मेदारी के विषय में भी प्रश्न हैं।

53. रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में, मैं इन मुद्दों पर वाद-विवाद का न केवल मैं स्वागत करता हूँ बल्कि इस पक्के विश्वास के साथ मैं इसे प्रोत्साहित भी करता हूँ कि ऐसा वाद-विवाद आम जनता के हित में है। विभिन्न समयों तथा विभिन्न संदर्भों में इस प्रकार के वाद-विवाद में मुद्दों का मैंने जवाब दिया है। इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा का यह अवसर और प्लेटफार्म नहीं है। यहां मैं केवल मोटे तौर पर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

54. पक्के तौर पर, रिज़र्व बैंक को जो जनादेश मिला है वह अधिकांश केंद्रीय बैंकों से व्यापक है। वह ऐसी व्यवस्था है जिसने देश की अर्थव्यवस्था की भलीभांति सेवा की है। रिज़र्व बैंक के जनादेश के विभिन्न घटकों में आपसी तालमेल है और हमें उन्हें गवां नहीं देना चाहिए। निश्चय ही, हमारे संस्थागत ढांचों को बदले रहे सामाजिक-आर्थिक संदर्भ के अनुसार अपने को अवश्य ढाल लेना चाहिए, किंतु इस बारे में विस्तृत वाद-विवाद तथा चर्चा के बाद ही इस प्रकार के बदलाव अवश्य किए जाने चाहिए।

55. विशेष रूप से 'दि इकानामिस्ट' ने अपने 2012 के अंक में एक पूरे फीचर में रिज़र्व बैंक के बारे में कहा है कि भारिबैंक पूरे विश्व में प्रचलित पूर्णकालिक सेवा वाले केंद्रीय बैंक के प्रकार का एक अनुकरणीय माडल है। उसमें कुछ ऐसा ही है।

56. यह बात भी महत्व की है कि रिज़र्व बैंक का जनादेश संविधि में लिखा गया है जिससे बदलती सरकारों के राजनीतिक व्यवहारों से वह सुरक्षित है।

57. आज अपने व्याख्यान के शुरूवाले हिस्से में, मैंने एक स्वायत्त केंद्रीय बैंक के लिए तर्क दिए। अधिकांश अन्य विकासशील देशों की तरह, रिज़र्व बैंक का जन्म स्वायत्त रूप में नहीं हुआ: अंतर्राष्ट्रीय अनुभव एवं हमारे राजनीतिक कार्यपालकों, जिन्होंने रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता बनाए रखने में फायदा देखा, की परिपक्वता की सीख के फलस्वरूप इसे अपनी स्वयत्तता मिली।

अपनी ओर से, रिजर्व बैंक ने यह स्वायत्तता अर्जित की। उसने व्यापक जनहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

58. उत्तरदायित्व स्वायत्तता से एकदम भिन्न एवं कम स्वागत योग्य है। रिजर्व बैंक अधिनियम में उत्तरदायित्व के लिए किसी प्रकार का औपचारिक तरीका नहीं निर्धारित किया गया है। फिर भी, वर्षों से कतिपय अच्छी प्रथाएं यहां डाली गई हैं। संक्षेप में, मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूँ। हमने अपनी नीतियों के पीछे तर्क को स्पष्ट किया और जहां संभव हो सका वहां उसके अपेक्षित परिणाम बताए। गवर्नर प्रत्येक तिमाही नीति की समीक्षा के बाद एक नियमित मीडिया सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें खुले मन से प्रश्न आमंत्रित किए जाते हैं, न केवल मौद्रिक नीति से संबंधित, बल्कि रिजर्व बैंक की गतिविधियों के पूरे क्षेत्र के बारे में भी।

59. रिजर्व बैंक अपने क्षेत्र से संबंधित संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए वित्त मंत्री को अपनी सेवाएं भी देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नर, जब कभी भी उसे बुलाया जाता है, वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होता है। वर्ष में ऐसी तीन से चार बैठकें होती हैं।

60. एक बात मेरे दिमाग में प्रायः आती है कि इस प्रकार के शक्तिशाली जनादेश वाले लोक नीति की संस्था के लिए उत्तरदायित्व के ये तरीके अपर्याप्त एवं बिना संरचना के दोनों ही हैं। संभवतः, हमें एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें गवर्नर वित्त संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सामने रिजर्व बैंक की नीतियों तथा उनके परिणामों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उक्त समिति के सदस्यों से प्रश्नोत्तर के विषय में वर्ष में दो बार जा सके। मेरे विचार से, इससे न केवल सुरक्षा के उत्तरदायित्व का ढांचा सुरक्षित रहेगा, बल्कि उसकी स्वायत्तता पर किसी प्रकार के संभावित आक्रमण से बैंक की सुरक्षा भी होगी।

61. स्वायत्तता एवं उत्तरदायित्व की इस अंतिम चुनौती पर मैंने कुछ विस्तार से ही चर्चा की। इसका कारण केवल यह है कि हमने इसके बारे में व्यापक जन क्षेत्र में उतनी चर्चा नहीं की जितनी की हमें करनी चाहिए। रिजर्व बैंक के स्टाफ के लिए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तरदायित्व निभाने के विषय में उसे (स्टाफ) उतना ही उत्साही होना चाहिए जितना की वे बैंक की स्वायत्तता की रक्षा के लिए हैं।

ईश्वर को धन्यवाद, रिजर्व बैंक विद्यमान है

62. स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के इस मुद्दे पर एक अंतिम विचार। सरकार तथा रिजर्व बैंक के बीच नीति संबंधी मतभेदों के

बारे में मीडिया ने काफी कवरेज किया है। जर्मन के पूर्व चांसलर, जेराड श्रोडर ने एक बार कहा था, “मैं प्रायः बुंडेस बैंक से हतोत्साहित हो जाया करता था, किंतु ईश्वर को धन्यवाद, वह विद्यमान है।” मुझे आशा है कि वित्त मंत्री, चिंदबरम एक दिन कहेंगे, “मैं रिजर्व बैंक से हतोत्साहित हूँ, इतना हतोत्साहित कि मैं टहलने के लिए जाना चाहता हूँ, भले ही मुझे अकेले ही टहलना पड़े। किंतु ईश्वर को धन्यवाद, रिजर्व बैंक विद्यमान है।”

निष्कर्ष

63. अपनी बात अब मैं समाप्त करता हूँ। इस व्याख्या के दौरान, पिछले पांच वर्षों की ओर मैंने दृष्टि डाली और इस बात की ओर संकेत किया कि कैसे नीति विषयक जटिल चुनौतियों को इस अवधि में अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया। मैंने रिजर्व बैंक की नीति संबंधी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया और व्यापक स्तर पर उस नीति संबंधी प्रतिक्रिया की कुछ आलोचना के बारे में मैंने प्रकाश डाला। इसके बाद, मैंने भविष्य की उन चार चुनौतियों पर विचार किया जिन पर रिजर्व बैंक को अवश्य विचार करना चाहिए ताकि वह एक उत्तरदायी, सुसंगत एवं बौद्धिक रूप से चुस्त-दुरुस्त नीतिवाली संस्था बनी रहे।

64. भारतीय रिजर्व बैंक में पांच वर्ष से कुछ अधिक समय तक सेवा करने के लिए मैं अत्यंत सौभाग्यशाली रहा हूँ। वे परेशानी के समय थे, परीक्षण के समय थे, चिंता के समय थे। लेकिन हर समय मैंने इस विश्वास के साथ काम किया की एक महान संस्था मेरे पीछे है और वह मुझे सही दिशा में ले जाएगी। मैं रिजर्व बैंक के स्टाफ और अधिकारियों की संव्यावसायिकता, बौद्धिक चुस्ती तथा प्रतिबद्धता से अत्यंत प्रभावित हूँ। यह एक ऐसी संस्था है जिसने देश की सेवा सम्मान एवं प्रतिष्ठा के साथ की और वह संव्यावसायिक ईमानदारी तथा कार्य-संस्कृति के लिए उपयुक्त मानक स्थिर करना जारी रखेगा।

धर्म

65. नानी पालखीवाला ने कहा था, “धर्म जनता के हृदय में रहता है: जब वह मरता है, कोई संविधान, कानून, संशोधन उसे बचा नहीं सकता।” यदि मैं इस सोच को थोड़ा विस्तार दूँ तो कह सकता हूँ कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध होता है जब उसकी लोक संस्थाएं धर्म से चालित हों। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की लोक संस्थाओं की सूची में सर्वोपरि है जो केवल धर्म और केवल धर्म से चालित होती है।